

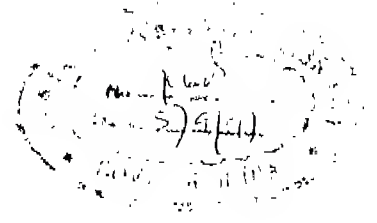


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I  
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 110 ]  
No. 110 ]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 1997/ज्येष्ठ 21, 1919  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 1997/JYAISHTHA 21, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 1997

**विषय:** यू.एस.ए. कनाडा तथा रूस से अखबारी कागज के आयात संबंधी पाटनरोधी जाँच—प्रारम्भिक निष्कर्ष

सं. 21/एडीडी/96:—1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके सीमाशुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन तथा वसूली एवं क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. क्रियाविधि

1. वर्तमान जाँच के बारे में निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाई गई है;
- क. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा) को उपर्युक्त नियमों के तहत इंडियन न्यूजप्रिंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन से लिखित रूप में याचिका प्राप्त हुई जिसमें यू.एस.ए., कनाडा तथा रूस मूल के अथवा वहाँ के निर्यातित अखबारी कागज की डंपिंग का आरोप लगाया गया है।
- ख. आवेदन की प्रारंभिक जाँच के कुछेक कमियों का पता चला था जो याचिकाकर्ता को बतला दी गई थीं।
- ग. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने यू.एस.ए., कनाडा और रूस (जिन्हें इसके बाद संबंधित देश कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित कथित रूप से डम्प किए गए आयातों के विरुद्ध जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकारी ने डंपिंग आरोप के प्राप्त होने के बारे में उपनियम 5 (5) के अनुसार जांच को शुरू करने के आदेश की कार्रवाई के बारे में संबंधित देशों के दूतावासों को सूचित कर दिया है।

- घ. प्राधिकारी ने दिनांक 20-12-1976 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई जिसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अधिसूचना -1 के अध्याय के अंतर्गत वर्गीकृत गू स्स र, कनाडा तथा स्स के मूल के अथवा वहाँ के निर्यातित अखबारी कागज के आयात के संबंध में पाटनरोधी कार्रवाई शुरू की थी ।
- ङ. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात निर्यातकों ॥ जिनके संबंध में ब्यौरे यापिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे ॥ तथा उद्योग धीरसंधों को प्रेषित की थी तथा नियम 6 ॥2॥ के अनुसार उनमें 40 दिन के भीतर लिखित में अपने विचारों को भेजने का अवसर प्रदान किया गया था ।
- च. प्राधिकारी ने भारत में अखबारी कागज के ज्ञात आयात को कौ सार्वजनिक सूचना की प्रतियाँ प्रेषित की थी और उन्हें इस पत्र की तारीख के 40 दिन के भीतर लिखित में अपने विचार भेजने की सलाह दी थी ।
- छ. केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड सी बी ई सी को जांच की अवधि के लिए अपेक्षित सभी बिल प्रविष्टियों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया बहरहाल सी बी ई सी में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।
- ज. प्राधिकारी ने उक्त नियम 6॥3॥ के अनुसार संबंधित देशों के दूतावासों तथा ज्ञात निर्यातकों को यापिका की प्रतियाँ भेजी थी ।
- झ. प्राधिकारी ने निम्नलिखित निर्यातकों के अपेक्षित सूचना जानने के लिए प्रश्नावलियाँ भी भेजी थी;

- स्वीडिशी ग्राइस इंक, कनाडा
- स्वीडिशी ग्राइस शेल्स कारपोरेशन, यू० स्स० र०
- बोपाटर मर्फी पेपर कं० लि० कनाडा
- सौसी पैम्पियन इंक, कनाडा
- डाइसोपा फोरेस्ट प्रोडक्ट्स लि० कनाडा
- स्टोरा फोरेस्ट इंडस्ट्रीज लि० कनाडा
- स्काईटिफकार फोरेस्ट कम्पलेक्स, स्स
- कोडोपागा पल्प एण्ड पेपर कम्बाइन, स्स

- सोली कांस्ट्रक् पल्प एण्ड पेपर कम्बाइन, स्स
- बालखना पल्प एण्ड पेपर कम्बाइन, स्स

निम्नीलिखित निर्यातकों ने बढ़ी हुई समयवृद्धि के भीतर प्रश्नावली के उत्तर भेजे

- एबीटीबी-ग्राइस इंक § इसके बाद इन्हें एबीटीबी कहा जा सगा § ।
- स्टोन कंसोलिडेटेड कार्पोरेशन, यू० स्स० ए०  
§ इसके बाद इन्हें स्टोन कंसोलिडेटेड कहा जा सगा §

- अ० अनेक निर्यातकों, आयातकों तथा उपभोक्ताओं ने समयवृद्धि के लिए अनुरोध किया प्राधिकारी ने 28-2-97 तक इस वृद्धि की अनुमति दी ।
- ट० नई दिल्ली में यू० स्स० ए०, कनाडा तथा स्स के दूतावासों को नियम 6 §2§ के तहत जाय शुरू करने के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचना दी थी कि वे अपने-अपने देश के निर्यातकों/ उपभोक्ताओं को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर भेजने की सलाह दें । फर की प्रति याचिका तथा निर्यातक की प्रश्नावली ज्ञात निर्यातकों उपभोक्ताओं की सूची के साथ दूतावासों को भी भेज दी गई थी ।
- ठ० भारत में अखबारी कागज के अत अनुबंधित रजेंटों तथा आयातकों को प्रश्नावली भेजी गई जिसमें नियम 6§4§ के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी गई थी ।
- ड० भारत में अखबारी कागज के अनेक आयातकों/उपभोक्ताओं ने प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति, प्रश्नावली तथा/या उत्तर भेजने के लिए समयवृद्धि का अनुरोध किया था 28 फरवरी, 1997 तक समयवृद्धि की अनुमति <sup>दी</sup> गई थी/तथापि, प्राधिकारी ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया था कि स्स कोई प्राधान्य नहीं है कि सभी इच्छुक पार्टियों के उत्तर की प्रतीक्षा की जाय अथवा उन इच्छुक पार्टियों को अतिरिक्त समय दिया जाय जिन्हें प्राधिकारी ने प्रथम <sup>प्रश्नावली</sup> कोई जानकारी नहीं मांगी अपितु वे अपनी ओर से अपना व्यवहार करने के इच्छुक हैं । अतः प्रश्नावली उन सभी पार्टियों को नहीं भेजी गई जिन्होंने अनुरोध किया था हालांकि प्रारंभिक अधिसूचना की एक प्रति भेज दी गई थी ।
- ढ० घरेलू उद्योग से संबंधित जानकारी याचिकाकर्ता से मांगी गई थी । याचिकाकर्ता ने निम्नीलिखित के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की;

- मैसूर पेपर मिल्स लि० ‖मैसूर या एम पी एम‖,
- नेपा लि० ‖नेपा‖
- तमिलनाडु न्यूजीप्रिंट एण्ड पेपर लि० ‖टी एन पी एल‖
- हिन्दुस्तान न्यूजीप्रिंट लि० ‖एच एन एल‖

ण प्राधिकारी ने प्रारम्भिक जाँच परिणाम के लिए जरूरी समझी गई जानकारी का सत्यापन किया ।

त सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों तथा याधिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर लागत जाँच की गई ताकि उत्पादन की अधिकतम लागत तथा भारत में अखबारी कागज के निर्माण एवं बिक्री की लागत का पता लगाया जा सके जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि क्या डीपिंग मार्जिन से कम प्रतिपादन शुल्क लगाना घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा ।

थ यह जाँच । अप्रैल, 1996 से 31 अक्टूबर, 1996 तक की अवधि के लिए की गई।

### ख :- याधिकाकर्त्ता के विचार

2 याधिकाकर्त्ता ने अपनी याधिका में जो प्रमुख मुद्दे उठाए हैं तथा बाद में अनुरोध किए हैं, वे इस प्रकार हैं ।

#### डीपिंग पर

संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और रूस ने अखबारी कागज की बड़े पैमाने पर डीपिंग के कारण अखबारी कागज उद्योग बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है । अखबारी कागज की डीपिंग के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी से भारतीय अखबारी कागज उद्योग को क्षति पहुंची है ।

सरकार की नीति में परिवर्तन के साथ अखबारी कागज के उत्तरी अमरीका तथा रूस के विनिर्माताओं ने अपनी कीमतों में भारी कमी की है ।

उत्तरी अमरीका में अखबारी कागज का सामान्य मूल्य कनाडा में एक उत्पादक

द्वारा पुष्ट की गई कीमतों द्वारा निर्धारित किया जाता है याधिकाकर्त्ता ने कनाडा और यू एस ए के घरेलू बाजार में अनेक निविदाएं-प्रस्तुत की हैं । याधिकाकर्त्ता ने दावा किया है कि य० एस० ए० और कनाडा के मामले में सामान्य मूल्य का स्तर एक समान माना जाना चाहिए और दोनों का एक ही राज्य क्षेत्र जाना चाहिए ।

- याधिकाकर्त्ता ने डंपिंग के अपने आरोप के समर्थन में निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु अनेक निविदाएं प्रस्तुत की । घरेलू बाजार में कीमतों के संबंध में निविदाएं भारत को किस तरह निर्यात की कीमत लगभग एक ही समय की थीं निविदाओं में समय-अंतराल बहुत कम या छि एक दिन है ।
- उत्तरी अमरीका के उत्पादकों द्वारा अखबारी कागज की डंपिंग 250 अमरीकी डालर प्रति मी० टन थी, स्स के मामले में यह कहा गया कि प्राधिकारी को लुगदी की अंतराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर स्सी उत्पादकों के लिए निर्धारित की गई उत्पादन लागत के आधार पर निकाले गए सामान्य मूल्य पर विचार करना चाहिए ।

### क्षति पर

- घरेलू उत्पादकों द्वारा बिक्री कीमतों में कमी किस जाने के बावजूद इन देशों के आयातों की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई । जिसके फलस्वरूप घरेलू उत्पादकों की बिक्री और क्षमता उपयोग बहुत कम हुआ ।
- कुछेक भारतीय उत्पादकों को अखबारी कागज के उत्पादन को तो पूरी तरह से बंद करना पड़ा अथवा काफी हद तक कम करना पड़ा ।
- समग्र रूप में आयात में वृद्धि होना आयात के घरेलू पेपर की तुलना में बाजार शेयर और क्षमता उपयोग में कमी होना डम्प किस तरह आयातकों द्वारा हुई भारतीय उद्योग को क्षति के प्रत्यक्ष प्रमाण है ।

ग. निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

-----

4. जिन निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों ने प्राधिकारी को उत्तर भेजा था उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार निम्नांकित हैं;

1. कनाडा उच्चायोग

डीपिंग पर

-----

- क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए डीपिंग के बारे में साक्ष्य अनिश्चित तथा अस्पष्ट हैं ।
- ख. शिकायत में दिखाई देता है कि विश्व भर में लुग्दी तथा कागज के उत्पाद की कीमतों में कमी हो रही है । यह तथ्य कि उत्तरी अमरीका के घरेलू बाजार में कीमतें तथा भारत को किए गए निर्यात की कीमतों में हो रही कमी इस बात का संकेत है कि डीपिंग नहीं हो रही है ।
- ग. शिकायत में विभिन्न स्थानों में प्रयुक्त सामान्य मूल्य के बीच विसंगतियाँ हैं ।
- घ. याचिकाकर्ता ने कहा है कि निर्यात के घरेलू बाजार में प्रचलित कीमतों में समायोजनों की आवश्यकता नहीं है ।
- ङ. याचिका में कनाडा के बाजार में बिक्री कीमतों से संबंधित कोई जानकारी नहीं है । शिकायत में सामान्य रूप से उत्तरी अमरीका में दो स्वतंत्र देशों की बनाय उत्तरी अमरीका के एक बाजार का उल्लेख किया गया है ।

क्षति और उसके कारण के बीच सम्बन्ध पर

-----

- क. याचिका में यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि हुई क्षति डीपिंग के कारण हुई है ।
- ख. कनाडा से निर्यात की कीमत 1994-95 की कीमतों से अब भी अधिक है । इस तथ्य में इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है कि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं ने अपनी कीमतों में जनवरी, 1996 के बाद से भारी कमी की है । शिकायतकर्ताओं को बिक्री तथा बाजार शेयर में जो नुकसान हुआ है वह डीपिंग को छोड़कर अन्य कारणों से हो सकता है ।

- ग. याचिका में इस बात का साक्ष्य है कि क्षति सामान्यतः अन्य कारणों से हुई हो । उदाहरण तथा पिछले वर्षों में विभिन्न आयात प्रतिबंध हटाय गये हैं । जो कि विदेशी आपूर्तिकर्त्ता बाजार में प्रवेश कर सकें । उपरोक्ताओं का विदेशी उत्पादकों की ओर झुकाव सामान्यतः अन्य कारणों से हुआ है जैसे गुणवत्ता, समय की पाबंदी, आपूर्ति की भरपूरता आदि एक उत्पादक ने जुलाई में काम बंद कर दिया जिससे ग्राहकों को सम्भवतः आपूर्ति की समस्या हुई होगी ।
- घ. यह तथ्य कि भारत में कुछ कंपनियां जो बंद हो गई हैं वे क्षति का संकेतक हैं इसे ठीक से जोड़ा जाना आवश्यक नहीं है । इनके बंद होने का कारण यह हो सकता है कि ये उत्पादक विदेशी सामान के अच्छे व्यापार के साथ <sup>प्रतिभाषित</sup> नहीं कर सके हैं । उपरोक्ता विदेश की आपूर्ति की ओर मुड़ सकता है क्योंकि वह स्थायी, दीर्घविव्ही <sup>स्थित है</sup> ।
- ड. सूचना की गोपनीयता के बारे में प्रधिकारी का स्पष्ट नहीं है ।

## II स्वीटिबी-प्राइस इंक

- क. भारत को निर्यात की कीमत विश्व के अन्य बाजारों को किस गर निर्यात की कीमतों अथवा कारखानागत घरेलू कीमतों की तुलना में वास्तविक रूप में कम नहीं थी ।
- ख. भारत को किस गर निर्यात तथा अंतरिक बाजार में की गई बिक्री के संबंध में स्वीटिबी चैन्डलर मिल के लिए लागत तथा लाभ प्रदत्त लगभग समान है तथा शेष विश्व को किस गर निर्यात पर हुई लाभप्रदता की तुलना में अधिक है ।
- ग. भारत को किस गर निर्यात तथा घरेलू बिक्री के लिए स्वीटिबी ग्रांड मिल की लागत तथा <sup>लाभप्रदता</sup> की तुलना करना कठिन है क्योंकि घरेलू बिक्री कोई हुई ही नहीं थी ।
- घ. जांच की अवधि के दौरान स्वीटिबी की कीमत का समायोजन ग्राहकों से प्राप्त बाजार मांग के प्रत्युत्तर में किया गया था ।
- ड. कंपनी द्वारा प्राप्त किस गर लाभप्रदक के स्तरों में कुछ उतार-चढ़ाव अलग-अलग मिल के आधार पर होंगे ।

111. स्टोन कैंमोली डेटिड कारपोरेशन, कनाडा प्राधिकारी द्वारा निर्यात को मूल रूप से संबोधित नहीं किया गया था। इससे यापिका तथा प्रसनावला की एक प्रति के लिए अनुरोध किया था और इसका उत्तर भेजा था। व्यक्त किए गए विचार निम्नानुसार हैं।

- क. यूरोपीय देशों में अखबारी कागज का पोत लंदन डम्प की गई कीमतों किया गया था।
- ख. संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा अलग-अलग देश हैं और उनसे अलग-अलग व्यवहार किया जाना चाहिए।
- ग. यापिकाकर्त्ता ने समुद्र का भाड़ा तथा अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा दोनों ही 130 अमरीकी डालर प्रति मी० टन बनाया जो सही नहीं है और बहुत ही अधिक है।
- घ. यापिकाकर्त्ता ने डीपिंग के साक्ष्य के लिए सूची कीमतों के आधार बनाए हैं। यह वह कीमत नहीं थी जिस कीमत पर कारोबार किया गया था।
- ङ. यापिका में विभिन्न प्रकार के विशोधाभास हैं।
- च. यापिकाकर्त्ता ने इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि कथित डीपिंग के फलस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षति कैसे हुई। यापिका में कारणात्मक सम्बन्ध का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- छ. भारत में अखबारी कागज के आयात को बड़े पैमाने पर नियंत्रित किया गया था जो मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन है।
- ज. अखबारी कागज की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुई।
- झ. अखबारी कागज के उद्योग की कीमतों में कथित रूप से अतार-चढ़ाव आया है।
- डू. भारत सरकार ने अखबारी कागज पर 10% का आयात शुल्क लगाया है।
- ट. कम क्षमता उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर प्रतिद्वंद्विता करने के लिए घरेलू उद्योग की असमर्थता का प्रत्यक्ष परिणाम है।
- ठ. भारतीय उद्योग के पास मई, 95 में आयात से नियंत्रण हटा लेने के फलस्वरूप स्टॉक का पर्याप्त भंडार था और फरवरी 96 में भी बहुत अधिक था जब कीमतें काफी अधिक थीं।



• **मैकर इंटरनेशनल कंसोर्टियम स्स {मैकर}**

---

भारत बाजार में प्रचलित अखबारी कागज की कम कीमतों पर पिता वयक्त करते हुए निर्यातक ने भारत में अखबारी कागज के बाजार का केवल सीक्षिप्त इतिहास ही दिया है ।

• **आयातक/उपभोक्ता तथा अन्य हितबद्ध पार्टियां**

---

इम्पिंग पर

- क. मांग और आपूर्ति की ताक्तों के कारण अप्रैल, 96 से सम्पूर्ण विश्व में अखबारी कागज की कीमतों में कमी आनी शुरू हुई थी ।
- ख. आयातकों पर से निर्यात समाप्त करने के बाद भी अखबारी कागज की कीमतों में भारतीय बाजार में वृद्धि हुई थी ।
- ग. जांच की अवधि के दौरान अखबारी कागज की कीमतों में निरंतर कमी आई है । प्रतिमाह की तुलना में यू० स्स० कीमतों तथा आयात कीमतों के बीच स्पष्ट संबंध की पुष्टि हो जाती है ।

### क्षति पर

- ॥ क॥ अखबारों कागज का अधिक आयात होना अन्य कारकों से जुड़ा है जैसे- गुणवत्ता, निर्भरता एवं समय पर आपूर्ति;
- ॥ ख॥ याधिकाकर्त्ता ने न तो नुकसान की मात्रा बताई है और न ही हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा दिया है। सामान्य मूल्य में उतार-चढ़ाव की वजह से क्षति नहीं होती है;
- ॥ ग॥ भारतीय उद्योग ने जाँच अवधि में भी काफी मुनाफा कमाया है;

### अन्य

- ॥ क॥ पाटनरोधी अधिनियम के प्रावधान एवं नियम लागू नहीं होते हैं। कीर्तित प्रावधान अधिकारों के विरुद्ध हैं, ये व्यापार एवं व्यवसाय करने के उपभोक्ताओं के अधिकार पर प्रतिबंध लगाते हैं और अखबारों कागज के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव का बर्ताव करते हैं;
- ॥ ख॥ उपभोक्ता उस मूल्य पर खरीदने की कोशिश करेंगे जो मूल्य उनके उत्पादन लागत से कम है।

### घ. उठाए गए मुद्दों की जाँच

- 5. निर्यातकों, आयातकों, याधिकाकर्त्ता, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा पेश किए गए कागजातों की जाँच की गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उन पर विचार दिया गया है और इस रिपोर्ट में उपयुक्त स्थलों पर उन पर कार्रवाई की गई है।

### ड. विद्याराधोन उत्पाद

- 6. वर्तमान जाँच में विद्याराधोन उत्पाद अखबारों कागज है। अखबारों कागज एक अनकोटेड किस्म का कागज है जो अखबार छापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें 65% से अधिक बजन में यांत्रिक अथवा रासायनिक-यांत्रिक प्रक्रिया से प्राप्त काष्ठ रेशा के तत्त्व मौजूद रहते हैं, वे बिना आकार अथवा बहुत की कम समान आकार के होते हैं जिनके दोनों छोरों पर असमतल पार्कर प्रोट स्पर्ट १। एम पी ए १ होता है जो 2.5 माइक्रो मीटर (माइक्रोन) से अधिक नहीं होता, और वजन में 40 ग्राम से कम तथा 65 ग्राम से अधिक नहीं होता। अखबारों कागज को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के अध्याय- 48 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जाँच के क्षेत्र के लिए बाध्यकारी नहीं है।

### घ. समान वस्तु

- 1. कुछ हितबद्ध पार्टियों ने तर्क दिया है कि अखबारों कागज का आयात जीर्ण देशों से इसकी गुणवत्ता की वजह से किया गया है। लेकिन इन हितबद्ध पार्टियों में यह विवाद नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं वितरित

अखबारों कागज का तथा इन देशों से आयातित अखबारों कागज का आदान-प्रदान कर इस्तेमाल किया गया है। इन देशों से किए गए आयात के तरीके और घरेलू उद्योग द्वारा इसकी बिक्री करने से यह बात स्पष्ट रूप से सुनिश्चित हो जाती है कि संबंधित देशों से आयातित अखबारों कागज का प्रतिस्थापन घरेलू उद्योग द्वारा तकनीकी एवं वाणिज्यिक दोनों रूप से उत्पादित एवं बिक्री किए गए अखबारों कागज के लिए किया। अतः नियम 2४४ के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं बिक्री किए गए अखबारों कागज को संबंधित देशों से आयातित अखबारों कागज के समान-वस्तु माना जा सकता है।

### छ. घरेलू उद्योग

11. यह यापिका इंडियन न्यूजप्रिंट मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन §आई एन एम ए४, डी- 165, रिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली- 24 द्वारा दायर की गयी है। इसलिये यापिका घरेलू उद्योग की ओर से दायर समझी जाती है।
12. एसोसिएशन ने उन घरेलू औद्योगिक इकाईयों के बारे में सूचना भेजी है जिनका जॉय अघी के दौरान भारत में कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है। ये इकाईयाँ नियम 2४४ के अनुसार संयुक्त रूप से घरेलू उद्योग का रूप लेते हैं।

### सामान्य मूल्य

12 धारा 9 §1४ के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है :

- §1४ व्यापार के सामान्य क्रम में, सामान वस्तु जब निर्यातक देश या क्षेत्र में उद्योग के उद्देश्य से है तो उसके लिए तुलनात्मक कीमत उप-धारा §6 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है, या
- §2४ जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान मिलती-जुलती वस्तु की बिक्री नहीं है, या जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति या बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना नहीं हो सकती है, तब सामान्य मूल्य निम्नांकित दोनों में से एक होगा :

- (क) समान वस्तु की तुलनात्मक प्रतिनिधि कीमत जबकि इसका निर्यात निर्यातक देश या क्षेत्र या एक उपयुक्त तीसरे देश से किया जाता है जिसका निर्धारण उपधारा §6 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है, अथवा
- (ख) उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत तथा उसमें प्रशासनात्मक बिक्री संबंधी और सामान्य लागतों तथा लाभों के लिए उचित कीमत जोड़ी जाती है, जिसका निर्धारण उपधारा §6 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है।

लेकिन धर्ता यह है कि उद्गम वाले देश से भिन्न किसी अन्य देश से वस्तु के आयात के मामले में जहाँ वस्तु को सिर्फ निर्यातक देश से होकर वाहनान्तरित किया गया या ऐसी वस्तु निर्यातक देश में उत्पादित नहीं की जाती है या निर्यातक देश

में कोई तुलनात्मक कीमत नहीं है, तब सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।

यह तर्क दिया गया है कि याचिका में कोई उचित साक्ष्य नहीं था और जिस आधार पर जांच शुरू की गई है वही उचित नहीं है । प्राधिकारी ने नोट किया है कि याचिकाकर्ता का यह दावित्व है कि वह प्रथम दृष्टया मामले को स्थापित करे । याचिकाकर्ता वे साक्ष्य देने के लिए कृत संकल्प है जो उसके पास आसानी से उपलब्ध है । वर्तमान मामले में याचिका कर्ता ने इस क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों के आधार पर सामान्य कीमत के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । याचिकाकर्ता ने प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित मूल्यों के आधार पर इस क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों का साक्ष्य दिया है ये साक्ष्य मूल्य सूची के आधार पर नहीं है । यह सराहनीय है कि पत्रिकाओं में प्रकाशित मूल्य कारखानागत वसूली के आधार पर नहीं है और इनमें समायोजन की अनुमति दी जा सकती है । तथापि, प्राधिकारी ने पाया कि प्रकाशित मूल्यों के आधार पर परिकल्पित सामान्य मूल्य और कारखानागत वसूली के आधार पर निर्यात मूल्य में पर्याप्त अन्तर है । जिसमें वे खर्च शामिल किए जा सकते हैं जिनके लिए निर्यातक ने घरेलू बाजार में बिक्री पर खर्च किया होगा । इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि जांच को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए उसके समक्ष सामान्य मूल्य के बारे में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है । निम्न व्यौरे के अनुसार प्राधिकारी ने इन प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में इन निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर कनाडा के निर्यातकों द्वारा की गई वास्तविक सकल वसूली के आधार पर कनाडा के मामले में सामान्य कीमत निर्धारित की है ।

11. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने समुद्री भाड़े तथा निर्यातक देशों में अन्तर्देशीय भाड़े के लिए अनुचित एवं अत्यधिक समायोजन का दावा किया है। चूंकि समुद्री भाड़े तथा अन्तर्देशीय भाड़े के संबंध में समायोजन निर्यातकों द्वारा दावा की गई रकम के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा किया गया दावा असंगत है ।

12. प्राधिकारी ने उपरोक्त धारा के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी ताकि उसके आधार पर सामान्य कीमत निकाली जा सके । जिन निर्यातकों ने सूचना भेजी है उनके मामले में सामान्य कीमत उनके द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर निकाली गई है और इसका व्यौरा नीचे दिया गया है :-

§1§ ए बी टी बी :

§1§ ए बी टी बी ने यू एस ए और कनाडा में अपनी मिलों के बारे में अलग उत्तर प्रेषित किया है । निर्यातक ने तर्क दिया है कि :

§क§ भारत को होने वाले निर्यात पर ए बी टी बी के वापस मिल की लागत एवं लाभ और गृह बाजार में बिक्री लगभग बराबर है और शेष विश्व को फिर गए निर्यात से प्राप्त लाभ से अधिक है ।

§ख§ एबीटीबी के ग्रांड मिल की लागत और लाभ जो तुलना भारत को होने वाले निर्यात पर लाभ आर घरेलू बिक्री से करना कीटन है , क्योंकि

- घरेलू बिक्री नहीं हुई है ,  
 §ग§ जाँच अधि के दौरान ए बी टी बी का मूल्य समायोजन उपभोक्ताओं को बाजार माँग के प्रत्युत्तर में था ।  
 §क§ अलग-अलग मिल के आधार पर कम्पनी द्वारा प्राप्त लाभ के स्तरों में कुछ अन्तर होगा ।

प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि निर्यातक ने यह निवेदन किया है कि लागत एवं लाभ आधार पर कोई डम्पिंग नहीं हुई है । निर्यातक का यह तर्क विधि के संगत प्रावधान को देखते हुए उचित नहीं है । डम्पिंग के लिए केवल निर्यातक के घरेलू बाजार में सामान्य मूल्य और भारत को होने वाले निर्यात मूल्य संगत है ।

§2§ निर्यातक का यह तर्क भी कि अलग-अलग मिल के लाभ में कुछ अन्तर हो सकता है जो उचित नहीं है । सामान्य मूल्य का निर्धारण दो बाजारों में सन्दर्भित मिल की कीमतों के अनुसार करना पड़ता है । चूंकि निर्यातक के पास कनाडा और यू एस ए में स्पष्ट रूप से अलग-अलग कीमतें हैं इसलिए यू एस ए और कनाडा से लिए गए निर्यातों पर अलग से कार्रवाई करनी होगी । अतः एचोटोबी के मामलों में आगे के पैराग्राफों में कनाडा और यू एस ए के लिए सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं ।

§3§ निर्यातक ने घरेलू बाजार में अपनी बिक्री मूल्यों के बारे में विस्तृत सूचना भेजी है । प्राधिकारी के अनुरोधानुसार सुचना महीना-दर-महीना आधार पर दी गई है । चूंकि निर्यातक ने घरेलू बाजार में अपने बिक्री मूल्य दिए हैं, इसलिए सामान्य मूल्य धारा 9 क §1§ से §1§ के अनुसार निर्धारित किया गया है ।

§4§ एचोटोबी ने घरेलू बाजार के मूल्यों में निम्नलिखित समायोजन करने का दावा किया है :-

§1§ छुट- निर्यातक ने दावा किया है कि उसने 780 अमरीकी डालर प्रति मो.टन के सूची मूल्य पर डिस्काउंट दिया है । यह डिस्काउंट जनवरी-मार्च, 1997 में \_\_\_\_\_ अमरीकी डालर था जो अक्टू. 1997 में \_\_\_\_\_ बढ़कर \_\_\_\_\_ अमरीकी डालर प्रति

मो. टन हो गया । चूंकि निर्यातक ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री पर डिस्काउंट दिया है, इसलिए प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजन के लिए उसी की अनुमति दी गई है ।

§2§ अन्तर्देशीय भाड़ा : निर्यातक ने तर्क दिया है कि अन्तर्देशीय भाड़ा अलग-अलग उपभोक्ताओं पर अलग-अलग होता है जो दूर पर निर्भर करता है । निर्यातक ने छर्चू हुए अन्तर्देशीय भाड़े की एक सीमा तक लागत का दावा किया है और उसने छर्चू किए गए भारतीय औसत अन्तर्देशीय भाड़ा लागत भी दर्शाई है । निर्यातक द्वारा बतलाई गई भारतीय औसत की अनुमति दी गई है ।

§5§ प्राधिकारी ने ऊपर दिए गए विवरण के अतिरिक्त प्रारम्भिक निर्धारण के उद्देश्य के लिए इन समायोजनों की अनुमति दी है । समायोजित मूल्यों की निम्न कारखानागत वसूली समझा गया है ।

स्टोन कन्सोलिडेटेड ने घरेलू मूल्यों में निम्नलिखित समायोजन करने का दावा किया है :-

छुट,

- घरेलू बाजार में भण्डार गृह से उपभोक्ताओं तक अन्तर्देशीय भाड़ा,
- समानता के आधार पर भिन्न से भण्डारगृह तक अन्तर्देशीय भाड़ा,
- बिक्री खर्चों में अन्तर,
- बेच प्रक्रिया के कारण उत्पादन लागत में अन्तर ।

§क§ छूट : निर्यातक ने अमरीकी डालर १ अप्रैल, 1997 से अमरीकी डालर १ अक्टू., 1997 प्रति मो. टन तक की छूट का दावा किया है । इस समायोजन की अनुमति मासिक आधार पर दी गई है ।

§ख§ अन्तर्देशीय भाड़ा : निर्यातक ने दावा किया है कि उसने अपने भण्डार गृह से घरेलू बाजार में बिक्री की है और अपने भण्डार गृह से ग्राहकों तक भाड़े पर अमरीकी डालर १ अप्रैल, 1997 से अमरीकी डालर १ अक्टू., 1997 तक छर्च किया है । निर्यातक ने यह भी दावा किया है कि उसने समान आधार पर अपने संग्रह से भण्डार गृह तक भी भाड़े पर अमरीकी डालर प्रति मो. टन का छर्च किया है ।

§ग§ घरेलू बाजार में बिक्री के लिए अतिरिक्त बिक्री छर्च होने से बिक्री छर्च के लिए अमरीकी डालर प्रति मो. टन के समायोजन का दावा किया गया है ।

§घ§ उत्पाद-लागतों में अन्तर के लिए अमरीकी डालर प्रति मो. टन के समायोजन का दावा इस आधार पर किया गया है कि घरेलू बाजार में बिक्री थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करनी पड़ती है और उपभोक्ता "बिल्कुल समय पर" सुपुर्दगी चाहते हैं । निर्यातक ने तर्क किया है कि घरेलू बाजार में बिक्री के लिए उसे किस्तों में उत्पादन करना पड़ता है । घरेलू बाजार में बिक्री को इस पद्धति के विपरीत निर्यातक पे यह भी तर्क दिया है कि भारत को निर्यात बड़ी मात्रा में होता है और भिन्न अन्धकारों कागज का उत्पादन अधिक समय तक लगातार कर सकते हैं । निर्यातक का तर्क है कि बेचों में उत्पादन करने में एक मशीन की उत्पादन क्षमता जहाँ सामान्यतः ४ होती है, वहाँ लगातार उत्पादन में उक्त क्षमता ४ होगी। उससे उत्पादन में ४ का अन्तर होगा । अतः निर्यातक का निष्कर्ष यह है कि घरेलू बाजार में बिक्री के मामले में अतिरिक्त लागत आती है जो औसतन कैनेडियन डालर प्रति मो. टन की निश्चित लागत १ के आधार पर १ के हिसाब से अनुमानतः अमरीकी डालर प्रति मो. टन होगी ।

निर्यातक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि बेचों में तथा निरंतर उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन क्षमता में अन्तर होगा । इसके अलावा निर्यातक द्वारा प्रस्तुत इस गए दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसे बेचों में उत्पादन करना पड़ा जबकि पार्टी ने दावा किया है कि उसने मात्र भण्डार गृहों से भेजा है । इसलिए निर्यातक के दावे को स्वीकार नहीं किया गया है ।

यद्यपि निर्यातक के दावे को विस्तृत जाँच करने की जरूरत है तथापि, प्राधिकारी ने प्रारम्भिक निर्धारण के प्रयोजन से §क§ से §ग§ तक इन दावों की अनुमति दी है ।

§उ§ कनाडा और यू एस ए से अन्य निर्यातक

मेसर्स मैकार्थी टेटरौल्ट, कनाडा ने अपने दिनांक 3 अप्रैल, 1997 के फैसले द्वारा सूचित किया है कि उसे समय पर इन्धुआरी के बारे में सूचना नहीं मिली और उसने 15 अप्रैल, 97 तक समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया ।

प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि नियम 6१4 के अंतर्गत प्राधिकारी निर्यातकों



विदेशों उत्पादकों से सूचना मंगाने के लिए नोटिस जारी कर सकता है और यह सूचना इस नोटिस को प्राप्ति को तारीख से तोम दिनों के भीतर इन ऐसे व्यक्तियों को भेजनी होगी। ऐसा माना जाता है कि यह नोटिस प्राधिकारी द्वारा अथवा निर्यातक देश के दूतावास को भेजे जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर भिज जाता है। इसीलिए प्राधिकारी ने निश्चय किया है कि मैक्सवेली टेटरौल्ट, कनाडा के समय को बढ़ाने के अनुरोध को मानना अनुचित होगा। तथापि, यदि सूचना भेजी गई तो प्राधिकारी निश्चित निर्धारण के लिए उस पर विचार करेगा।

कनाडा और यू एस ए के अन्य उत्पादक/निर्यातक प्राधिकारों को सूचना भेजने में असफल रहे हैं। प्राधिकारी यह निश्चय किया है कि कनाडा और यू एस ए के अन्य निर्यातक/उत्पादक प्राधिकारों के सहयोग देते हैं असफल रहे और नियम 68B के अनुसार प्रारम्भिक निष्कर्षों की घोषणा कर दी गई है।

आयातकों द्वारा दी गई सूचना की जांच से पता चलता है कि जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित पार्टियों ने भी भारत को अख्तारों कागज का निर्यात किया :

॥क॥ प्राइस एण्ड पोस, 21-ए, नेल रोड, सिंगापुर

॥ख॥ सबनर इंक, 1250, रेने लेवेस्क बिल्टड बैस्ट, कोन्ट्रियल, क्वेबेक, कनाडा

॥ग॥ रेशोवा फोरेस्ट प्रोडक्ट्स, कनाडा।

चूंकि इन निर्यातकों ने प्राधिकारों को सहयोग नहीं दिया, इसलिए जांच की शुरुआत के समय परिष्कृत सामान्य भूतल पर विचार किया गया है। चूंकि इस बात का समुचित साक्ष्य है कि निर्यातकों ने घरेलू बाजार में की गई बिजली पर भाड़े का भुगतान किया है, इसलिए 40 अमरीकी डॉलर प्रति की. टन के हिसाब से इसकी अनुमति दी गई है।

॥4॥ मेकर ने यह कहे हुए सूचना नहीं भेजी है कि उसके पास पृथी गयी कोई जानकारी नहीं है। प्राधिकारों ने सूचना मंगाने हुए नोटिस में साफ तौर पर कहा था कि निर्यातक ने यदि निम्नलिखित कोई कार्य नहीं किया है तो नोटिस को संबंधित पार्टी के पास भेज दिया जाय :-

॥क॥ विद्याराधोन सामान का उत्पादन अथवा विनिर्माण करता है,

॥ख॥ घरेलू बाजार में बेचता है,

॥ग॥ भारत को निर्यात करता है,

॥घ॥ भारत को छोड़कर अन्य देशों को निर्यात करता है।

उपरोक्त को देखते हुए, मेकर को यह प्रस्तावती संबंधित पार्टियों/पार्टियों को भेजनी चाहिए थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तथापि, मेकर ने भारतीय बाजार में प्रचलित कम कीमतों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह कीमतों में सुधार लाने के लिए उपाय करें।

॥5॥ भारत में स्लो व्यापार प्रतिनिधि परिसंघ ने अपने दिनांक 30.12.76 के पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि प्राधिकारों विदेशों आर्थिक संबंध मंत्रालय, मास्को/रूस को सूचना मंगाने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। तदनुसार, प्राधिकारों ने विदेशों आर्थिक संबंध मंत्रालय, मास्को, रूस तथा भारत में स्लो व्यापार प्रतिनिधि परिसंघ को नोटिस जारी किया। तथापि प्राधिकारों नोट करता है कि रूस के रूसी भी

निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में कोई सूचना नहीं भेजी है। प्राधिकारी मानते हैं कि रूस के निर्यातकों/उत्पादकों ने प्राधिकारी को कोई सहयोग नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी नियम 6१८१ के अनुसार प्रारम्भिक निष्कर्षों की घोषणा करते हैं।

चूँकि किसी भी निर्यातक ने उत्तर नहीं भेजा है इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण रूस के लिए निकाली गई उत्पादन लागत के आधार पर किया है। रूस के लिए उत्पादन लागत पहले जांच शुरू करने के समय निकाली गई थी। प्राधिकारी ने रूस के निर्यातकों/उत्पादकों से सहयोग नहीं मिलने के कारण प्रारम्भिक निष्कर्ष के लिए भी सामान्य मूल्य के उसी स्तर पर विचार किया है।

### एच० निर्यात मूल्य

18०. एबोटोबी और स्टोन कन्सोलिडेटेड के मामले में प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्यात मूल्य निकाला है। निर्यात मूल्य निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार निकाला गया है :-

एबोटोबी : निर्यातक ने कनाडा और यू एस ए से क्रिस् गस अपने निर्यात के पृथक ब्यौरे

दिए हैं। निर्यातक ने बीजक तारीख के आधार पर दोनों देशों से क्रिस् गस कारोबार-वार निर्यात के आंकड़े दिए हैं। निर्यातक द्वारा दिए गए महीनावार निर्यात ब्यौरे के आधार पर महीना-वार सी आई एफ निर्यात मूल्य निकाला गया है। निर्यातक ने निम्नलिखित समायोजन क्रिस् जाने का दावा किया है :-

### 14 - क

१क१ अन्तर्देशीय भाड़ा : यू एस मिल्स से क्रिस् गस निर्यातों के मामले में अमरीकी डालर प्रति मो० टन की राशि का दावा किया गया है जबकि कनाडा से क्रिस् गस निर्यातों के मामले में अमरीकी डालर प्रति मो० टन की राशि का दावा किया गया है।

१क२ समुद्री भाड़ा : यू एस मिल्स से क्रिस् गस निर्यातों के मामले में अमरीकी डालर प्रति मो० टन की राशि का दावा किया गया है जबकि कनाडा से क्रिस् गस निर्यातों के मामले में अमरीकी डालर प्रति मो० टन की राशि का दावा किया गया है।

१क३ कमीशन : निर्यातक ने दावा किया है कि उसने अमरीका से क्रिस् गस निर्यात के मामले में X को दर से डिस्काउंट दिया है और कनाडा से निर्यात के मामले में X को दर से/सौदे बार क्रिस् गस विवरण से यह पाया गया है कि निर्यातक ने कनाडा से हुए निर्यात के मामले में X से X के बीच कमीशन का भुगतान किया है। अधिकांश सौदों में X कमीशन दिया गया है। प्राधिकारी कमीशन के संबंध में क्रिस् गस दावे की अनुमति देना उचित समझता है।

प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानता है कि प्रारम्भिक जांच परिणाम के प्रयोजन से १क१ से १क३ तक समायोजन की अनुमति दे दी जाए।



—निर्यातक ने दावा किया है कि उसने यू एस से किस गस निर्यात के मामले में 1.625% तथा कनाडा से हुए निर्यात के मामले में 2.0% की दर से कमोशन का भुगतान किया है। सौदेवार ब्यौरे से पता चलता है कि निर्यातक ने कनाडा के मामले में 1.25% और 2.00% के बीच कमोशन का भुगतान किया है। अधिकांश लेन-देन 2.00% कमोशन पर किया गया है। तथापि, कमोशन के बारे में दावे पर विचार करने की अनुमति देना उचित है। प्रारम्भिक निष्कर्षों के प्रयोजन से अन्य समायोजनों पर विचार करने की अनुमति देना उचित है।

स्टोन कन्सोलिडेटेड :

§क§ स्टोन कन्सोलिडेटेड ने भारत को 96 में यू एस डालर प्रति मो. टन तथा 96 तक यू एस डालर प्रति मो. टन की दर से अच्छारी कागज का निर्यात किया, जबकि जांच अवधि के प्रत्येक महीने में घरेलू बाजार में निर्यातक के मूल्यों में गिरावट रही।

§ख§ निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उसने भारत को सभी निर्यात अपने एक मात्र ऐजेंट, मैसर्स यूनीवर्सल पेपर एक्सपोर्ट कं. लि., कनाडा के जरिए किस और भारत में कोई ऐजेंट नहीं था। निर्यातक ने आगे और कहा है कि उसने यूनीवर्सल को कारखानागत मूल्य पर % की दर से कमोशन दिया। निर्यातक ने भारत को किस गस निर्यातों के मामले में दिस गस समुद्री भाड़े तथा अन्तर्देशीय भाड़े का ह्योरा दिया है। समुद्री भाड़े के बारे में समायोजन का दावा निर्यातक द्वारा दिस गस देय वास्तविक समुद्री भाड़े के आधार पर किया है। अन्तर्देशीय भाड़े के संबंध में समायोजन का दावा प्रति कन्टेनर भाड़ा लागत अथवा प्रति कन्टेनर औसत भार पर आधारित है।

§ग§ कारखाना गत निर्यात मूल्य का परिकलन निर्यातक द्वारा की गई उपर्युक्त सुचना से किया गया है।

यू स्त र तथा क्नाढा से अन्य निर्यातक तथा स्त से निर्यातक

॥क॥ कनाहा और यू स्त ए से अन्य उत्पादक/निर्यातक और त्स से सभी निर्यातक/उत्पादक प्राधिकारी को जवाब देने में असफल रहे हैं । प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि ये प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में असफल रहे है और प्रारंभिक जांच-पड़नामों की घोषणा नियम 6 ॥8॥ के अनुसार कर दी गई है ।

॥ख॥ एघनर देशों का षण्ठ प्राइस षण्ठ पीस के मामलों में निर्यात मूल्य का सुनिश्चय आयातकों द्वारा दी गई सूचना से किया गया है । अलग-अलग निर्यातकों के मामले में औसत सी षण्ठ सफ़ निर्यात मूल्य में समुद्री भाड़ा, अन्तर्देशीय भाड़ा तथा कमीशन का समायोजन तथा द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर किया गया है । प्रीक निर्यातकों ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है, इसलिए तथा द्वारा किस्म गश् खर्च में से जो खर्च अधिक था उस पर विचार किया गया है ।

§४४ स्त के मामले में निर्यात मूल्य का निर्धारण वाणिज्यिक आसूचना एवं सॉल्वि की महानिदेशालय कलकत्ता द्वारा संकीर्ण सूचना के आधार पर किया गया है। चूंकि स्त से किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया इसलिए अलग-अलग निर्यातकों के मामलों में निर्यात मूल्य नहीं निकाला गया है। ती स्पष्ट एक निर्यात मूल्य में समुद्री भाड़े तथा कमीशन के लिए समायोजन किया गया है। याचिकाकर्त्ता ने—अमरीकी डालर प्रति मी टन की दर से समुद्री भाड़े का तथा ४ की दर से कमीशन का दावा

१६। तथापि किया गया कमीशन ४ ४ ४ ४ अधिक ४ इतलिर अमरीको डालर  
 यह पाया गया प्रीत मो टन की दर से भाड़े तथा ४ दर से कमीशन की अनुमति देना उचित समझा  
 है कि स्पर्धिक  
 अडा किया गया है ।

तुलना

तुलना

तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार प्रावधान है ।

“डॉरिंग का मार्जिन” निकालते समय, नामित प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा। यह तुलना व्यापार के उसी स्तर पर सामान्यतया कारखाना द्वार स्तर पर की जायेगी और यथासंभव उसी समय बिज्जी के संबंध में की जायेगी। जो अन्तर तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर छूट दी जायेगी; अन्तर में शामिल हैं - बिज्जी की शर्त, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, वास्तविक विशेषांतर तथा कोई अन्य अन्तर जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित

करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है" जबकि यह तर्क कि अन्तराष्ट्रीय बाजार में गिरावट आ रही थी इस बात को मानते हुए इसकी अच्छी प्रशंसा की जा सकती है लेकिन जहाँ तक निर्यातक द्वारा ठम्प किस जाने का संबंध है उसके बारे में यह बात <sup>असंगत है</sup> ठम्पिंग का निर्णय करने वाला एक मात्र आणविक मुद्दा दो विभिन्न बाजारों में निर्यातकी कीमत है। हितबद्ध पार्टियों का यह तर्क कि गिरती हुई अन्तराष्ट्रीय कीमतों के कारण कोई ठम्पिंग नहीं हुई थी, युक्ति संगत नहीं है। तथापि प्राधिकारी ने यह पाया है कि एबीटीबी तथा स्टोन कन्सोलिडेटेड के मामले में घरेलू बाजार में भी कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट आई। चूँकि यूएस और कनाडियन बाजारों में भी कीमतें कम हो रही थी इसलिए जाँच अर्पण के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के औसत के आधार पर कोई तुलना उपग्राह कर सकती है। जाँच प्रारम्भ करने का निर्णय लेने के उद्देश्य के लिए भी प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की तुलना निर्यात कीमत से माह दर माह आधार पर की थी। प्राधिकारी एबीटीबी तथा स्टोन कन्सोलिडेटेड द्वारा दी गई सूचना से यह मानता है कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना माह दर माह आधार पर करना उचित होगा। यह भी देखा गया है कि एबीटीबी और स्टोन कन्सोलिडेटेड ने भारत को किस गर निर्यात के सभी सौदों के ब्यौरे दे दिए हैं। इनके आधार पर निर्यात कीमत की तुलना यूएस/कनाडा में सामान्य मूल्य के साथ की गई है ताकि तुलना जहाँ तक संभव हो उसी समय हिन्दु के आस-पास की हो सके।

19. अन्य निर्यातकों के मामलों में निर्यात मूल्य की तुलना सामान्य मूल्य के साथ इसी प्रकार से अर्थात् माह दर माह आधार पर की गई है।

20. इस तुलना से निम्नलिखित ठम्पिंग मार्जिन दिखाई देता है :-



३. निर्यातक का नाम एन सी, ई पी, डी एम

6. कनाडा से ग्राइस रेंड पीस एन सी

ई पी  
डी एम  
एन सी

७. यू एस ए से ग्राइस रेंड पीस

ई पी  
डी एम

अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
17	32	30	42	24	51	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
56	38	...	...	...	...	...

## एन सी : सामान्य कीमत

ई पी : निर्यात मूल्य

डी एम : निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में डीएमएन मार्जिन

डीएमएन मार्जिन के बारे में डून्ग संख्या डून्ग आयात दर्शाता है जिसके फलस्वरूप डीएमएन मार्जिन डून्ग है

## क्षति

उक्त नियम 11 अनुबंध-2 के अंतर्गत जब क्षति का निष्कर्ष निकाला जाता है तो ऐसे निष्कर्ष में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निर्धारण भी शामिल होगा। ऐसा करते समय सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा जिनमें शामिल हैं—ठम्प किए गए आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव कीमतों पर ठम्प किए गए आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इसकी यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में ठम्प किए गए आयातों द्वारा कीमतों में पर्याप्त कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में कीमतों का अन्यथा कम करना या कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी बढ़ गई होती

नियमों का अनुबंध 10 का नियम 11.1 यह मांग करता है कि यदि एक से अधिक देशों से होने वाले उत्पाद के आयात की प्रतिपादन जांच होती है तो नामित प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संघीय मूल्यांकन करेगा। तथापि ऐसा मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब यह सुनिश्चित हो जाए कि।

§क§ प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में डंपिंग का मार्जिन 2% से अधिक है जो निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त होगा तथा प्रत्येक देश से होने वाले आयात की निर्यात कीमत तथा मात्रा भारत में समान वस्तुओं के आयात का 3% हैं; और

§ख§ आयातित सामान तथा उसके पैके ही घरेलू सामान के बीच प्रतियोगिता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए आयात के प्रभाव का संघीय मूल्यांकन उपयुक्त है।

मौजूदा मामलों में, प्रत्येक निर्यातक और साथ ही प्रत्येक देश के संबंध में डंपिंग मार्जिन दी गई सीमा से अधिक है। उसके अलावा आयात के प्रभाव का संघीय मूल्यांकन आयातित सामान तथा उसके पैके ही घरेलू सामान के बीच प्रतियोगिता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है। इसलिए प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर इन आयातों के प्रभावों का संघीय मूल्यांकन कर सकता है।

24- भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभावों की जांच करने के लिए उमर नियम के अनुबंध 11.1/1 के अनुसार प्राधिकारी ने ऐसे सूचकांकों पर विचार किया जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। जैसे उत्पादन क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा स्टाक, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री आय, डंपिंग की मात्रा तथा मार्जिन आदि का प्रभावित करते हैं।

§क§:- ठम्प आयातों की मात्रा तथा बाजार हिस्सा

§1§ ठम्प आयातों की मात्रा:-

भारत में अखबारों का आयात 217108 मी० टन §1992-93§ से बढ़कर 311967 मी० टन §1995-96§ हो गए और सात महीने की जांच अवधि में 382861 मी० टन के संबंधित देशों से आयात सामूहिक रूप से 108339 मी० टन §1992-93§ से बढ़कर 228899 मी० टन §1995-96§ हो गए और जांच अवधि के दौरान यह 284995 मी० टन के थे।

संबंधित देशों से आयात 1992-93 की तुलना में जाँच अवधि में निरपेक्ष रूप से 35% तक बढ़े जैसा कि पित्र -1 से देखा जा सकता है । देश के कुल आयातों में संबंधित देशों का हिस्सा 50% [1992-93] से बढ़कर 74% [जाँच अवधिमें] हो गया । भारत में अख्त्यारी कागज की कुल मांग में संबंधित देशों का बाजार हिस्सा 21% [1992-93] से बढ़कर 32% [1995-96] और जाँच अवधि में 54% हो गया जैसा कि पित्र -2 से देखा जा सकता है ।

ख. घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक

### §1§ उत्पादन तथा क्षमता उपयोग

घरेलू उद्योग का उत्पादन 1992-93 और 1995-96 के बीच 2.80 लाख और 2.90 लाख के बीच रहा । जाँच अवधि में उत्पादन में 12% तक वृद्धि हुई तथापि यह ध्याना योग्य है कि टी स्न पी स्ल की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है [50,000 मी टन की घरेलू उद्योग ने 47% [1992-93] से 40% [1995-96] तक बाजार हिस्सा खोया । तथापि जाँच अवधि में बाजार हिस्सा तेजी से गिर कर 17% रह गया जैसा कि पित्र -3 से देखा जा सकता है । याचिकाकर्ता ने सुचना दी है कि मैसर्स नेपा लि०, कनालक्ष्मी पेपर मिल्स लि० तथा औरंगाबाद पेपर मिल्स लि० ने डम्पिंग की प्रवृत्ति से रोकते हुए उत्पादन बंद कर दिया है ।

### §1.1§ सम्पूर्ण मात्रा में बिक्री :

सम्पूर्ण मात्रा में घरेलू उद्योग की बिक्री 1992-93 और 1995-96 के बीच 2.70 लाख मी० टन और 2.95 लाख मी० टन के बीच रही । तथापि बिक्री जाँच अवधि में वार्षिक आधार पर 45% तक तेजी से गिरी जैसा कि ऊपर के चित्र से देखा जा सकता है ।

### §1.1.1§ बिक्री कीमत प्रवृत्ति

घरेलू उद्योग संबंधित देशों से सस्ते आयातों के कारण अपने उत्पाद को बेचने में सफल नहीं हुआ । उपभोक्ताओं ने अन्य स्रोतों से उपलब्ध सस्ते उत्पाद की वजह से कम कीमतों और अधिक छूट की मांग की । जाँच अवधि में निर्यातक द्वारा लगातार कम कीमतों की पेशकश ने घरेलू उद्योग की अधिक छूट देने के लिए मजबूर किया, जिनके परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में कीमतों को कम करना पड़ा । यह भी नोट किया गया कि जाँच अवधि के दौरान प्रमुख कच्ची सामग्री वस्त्र के अन्तराष्ट्रीय मूल्यों में भी गिरावट आई । तथापि यह देखा जा सकता है कि जाँच अवधि के दौरान उत्पादन लागत में गिरावट की तुलना में बिक्री कीमतें उनी रही ।

§1.1.2§ स्टॉक :--- घरेलू उद्योग के महीने के अंत के स्टॉक जाँच अवधि के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति का संकेत करते हैं जैसा कि चित्र से देखा जा सकता है । नेपा के पास अख्त्यारी कागज के बिक्री योग्य स्टॉक मौजूद थे । कम्पनी द्वारा कामबन्दी निर्यातक के लिए भारत में कस्तुर डम्प करने का कोई कारण नहीं हो सकता ।



## ॥१॥ लाभ/हानि

घरेलू उद्योग जपि अवधि से पहले लाभ कमा रहा था । तथापि, घरेलू उद्योग को जपि अवधि के दौरान उत्पादन लागत और उचित लाभों से कम कीमतों पर अख्त्यारी कागज की बिक्री से वित्तीय हानियाँ हुई हैं ।

**क्षति का निष्कर्ष :-** उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष पर पहुँचा है कि:

॥१॥ संबंधित देशों से आयात निरपेक्ष रूप से बढ़े हैं;

॥१॥ उत्तरवर्ती महीनों में दी जाने वाली छिलीचरी के लिए लगातार कम दरों पर अख्त्यारी कागज की आपूर्ति के लिए निर्यातकों ने सम्झौते किए । इससे भारतीय उपभोगता को अपनी कीमती उत्पादन लागत तथा उचित लाभ से काफी कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा ।

॥१॥ संबंधित देशों से आयातों के परिणामस्वरूप भारतीय बाजारों में कीमतों में कमी हुई ।

॥१॥ घरेलू उद्योग की बिक्री जपि अवधि के दौरान तेजी से गिरी ।

॥१॥ घरेलू उद्योग के पास अख्त्यारी कागज के स्टॉक जपि अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाते हैं ।

38- इस प्रकार यह देखा गया है कि संबंधित देशों से होने वाले आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

## कारणात्मक संबंध

कम आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग को आर्थिक हानि हुई या नहीं, इसका निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखा:

॥१॥ सम्बद्ध देशों से इस उत्पाद के आयात में समग्र रूप से तथा भारत में इस उत्पाद के उत्पादन और खपत के संदर्भ में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । सकल उत्पाद में सम्बद्ध देशों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । इसके सीधे परिणाम के रूप में घरेलू उद्योग के बाजार स्तर में महत्वपूर्ण गिरावट आई ।

॥१॥ सम्बद्ध देशों से अख्त्यारी कागज के कम किए गए मूल्य पर वास्तविक आयात ने घरेलू उद्योग को अपने विपक्ष मूल्य को अलाभकारी स्तर तक कम करने के लिए बाध्य किया है और इसके परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में कीमत को कम करने की स्थिति बन गयी है । उत्पादन लागत से कम कीमत पर बिक्री के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ ।

इस प्रकार प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति सम्बद्ध देशों से कम किए गए आयात के कारण हुई ।



## §2॥ भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

सामान्य रूप से प्रति-पाटन शुल्कों का उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है तथा भारतीय बाजार में खुली और बिना भेदभाव की प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः बहाल करना है जो कि देश के सामान्य हित में है।

यह माना जाता है कि प्रति-पाटन शुल्क लगाने से अखबारी कागज से विनिर्मित उत्पादों की कीमत के स्तर प्रभावित हो सकते हैं और तदुपरान्त इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु प्रति-पाटन उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी विशेषकर तब जब कि प्रतिपाटन शुल्क को उस राशि तक सीमित रखा जाए जो घरेलू उद्योग की क्षति की पूर्ति करने के लिए आवश्यक हो। इसके विपरीत, प्रतिपाटन उपायों को लागू करने से पाटन क्रिया द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाये, यह घरेलू उद्योग की अवनीति को रोकेंगा और उपभोक्ताओं को ज्यादा विस्तृत पसंद की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करेगा। प्राधिकारी ने नोट किया है कि प्रतिपाटन उपायों से किसी भी तरह से सम्बद्ध देशों से होने वाले आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिपाटन शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तथा घरेलू उद्योग के लिए उचित लाभ को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग के लिए भारत में संबद्ध उत्प्रेरक मर्दों के उचित बिक्री मूल्य पर निर्भर रहना पड़ा।

भारत सरकार द्वारा लगाया गया आयात शुल्क घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि की मात्रा के निर्धारण के लिए संगत है और तदनुसार इसको ध्यान में रखा गया है।

यह अनुभव किया गया है कि अखबारी कागज उद्योग आवर्ती किस्म का है और समय-समय पर इसको उतार-चढ़ाव होता रहता है। किन्तु जैसा कि ऊपर तुलना के अन्तर्गत बताया गया है पाटन का निर्धारण सामान्य मूल्य और लगभग एक ही समय में किए गए निर्यात के मूल्य के संदर्भ में किया जाता है। इसलिए उद्योग का आवर्ती स्वरूप पाटन के निर्धारण के लिए संगत है।

32. जहाँ तक एक पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि गोपनीयता संबंधी नियमों में यह दिया गया है कि यदि प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध का कोई औचित्य नहीं है अथवा सूचना देने वाला या तो उक्त सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता या उसे सामान्य स्तर से उजागर करने का अधिकार नहीं सौंपना चाहता तो वह इस प्रकार की सूचना को रद्द कर सकता है। नियंत्रक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली में में टाइप की गलती है और "रिगार्ड" शब्द के स्थान पर "डिसरिगार्ड" रखा जाए।

### द. निष्कर्ष

33. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि:

- क. यू एस ए, कनाडा और स्वीडन के या वहाँ से निर्यातित अखबारी कागज का भारत को निर्यात इसकी सामान्य कीमत से कम कीमत पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है ;
- ख. इन देशों से अखबारी कागज के आयात से घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।
- ग. सम्बद्ध देशों से आयात के कारण क्षति हुई है।

घरेलू उद्योग की आर्थिक क्षति को समाप्त करने के लिए जाँच परिणाम के लम्बित रहने तक, सम्बद्ध देशों के या वहाँ से निर्यात किए गए अखबारी कागज के सभी आयात पर अन्तिम जाँच परिणाम आने तक, अनन्तिम स्तर से प्रतिपाटन शुल्क लगाना आवश्यक समझा गया है।

इस बात पर विचार किया गया कि डीम्पिंग मार्जिन से कम शुल्क लगाना हानियों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। इस उद्देश्य से प्रत्येक निर्यातक के लिए आयातों की पहुँच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की उस उचित बिक्री कीमत से की गई जिसका निर्धारण जाँच-अवधि के लिए किया गया है। जहाँ यह अन्तर डीम्पिंग मार्जिन से कम था, वहाँ डीम्पिंग मार्जिन से कम शुल्क की अनुशंसा की गई। तदनुसार प्राधिकारी यह सिफारिश करता है कि अन्तिम निर्धारण के लम्बित रहने तक इन देशों के या इन देशों से निर्यात किए गए, सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 48 के अन्तर्गत आने वाले अखबारी कागज के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना की

तिथि से वे अनन्तिम शुल्क लगाए जाएं जो कि नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं :

निम्नलिखित मूल के या वहां के निर्यातित उत्पाद	निर्यातक का नाम	शुल्क की राशि ₹ ल० प्रति मी० टन॥
1. यू.एस.ए.	क. एबीटीबी प्राइस इंक,	6250
	ख. प्राइस एण्ड पोस	2513
	ग. उपर्युक्त से भिन्न निर्यातक	6250
2. कनाडा	क. एबीटीबी प्राइस इंक	3089
	क. स्टोन कंसोलिडेटेड कारपोरेशन,	1041
	ख. देशावा फोरेस्ट प्रोडक्ट्स	2692
	ग. प्राइस एण्ड पोस	5160
	घ. उपर्युक्त से भिन्न निर्यातक	5160
3. स्त	कोई भी निर्यातक	3191

36. प्राधिकारी द्वारा ज्ञात आयातकों, निर्यातकों, व्यापकाकर्ताओं तथा अन्य हित-बद्ध पक्षों से अलग से अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस पत्र के जारी होने की तारीख से 40 दिन के भीतर अपने विचार भेज दें। अन्य कोई इच्छुक पार्टी भी इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन के भीतर अपने विचार भेज सकते हैं।

दीपक चटर्जी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th June, 1997

**Subject :** Anti dumping investigation concerning imports of newsprint from USA, Canada and Russia - Preliminary Findings

**No. 21/ADD/96:—**Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

**A. PROCEDURE**

1. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:
  - a. The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received written petition from Indian Newsprint Manufacturers Association alleging dumping of newsprint originating in or exported from the USA, Canada and Russia;
  - b. The preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were pointed out to the petitioners;
  - c. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner, decided to initiate investigations against alleged dumped imports originating in or exported from the USA, Canada and Russia (hereinafter referred to as the subject countries). The Authority notified the Embassies of the subject countries about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rules;
  - d. The Authority issued a public notice dated 20-12-1996, published in the Gazette of India, extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of newsprint, classified under chapter 48 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from USA, Canada and Russia;
  - e. The Authority forwarded copy of the public notice to the known exporters (whose details were made available by the petitioner) and industry associations and gave them an opportunity to make their views known in writing, within forty days, in accordance with the rule 6(2);

- f. The Authority forwarded copies of the public notice to the known Importers of newsprint in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the letter;
- g. Request was also made to the Central Board of Excise & Customs (CBEC) to arrange copies of all the relevant Bills of Entries for the period of investigation. No information has, however, been received from the CBEC;
- h. The Authority provided copies of the petition to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with rule 6(3) supra;
- i. The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information to the following exporters:
- Abitibi Price Inc., Canada,
  - Abitibi Price Sales Corp., USA,
  - Bowater Mersey Paper Co. Ltd., Canada,
  - Soucy Champion Inc., Canada,
  - Daishowa Forest Products Ltd., Canada,
  - Stora Forest Industries Ltd., Canada,
  - Skytyvkar Forest Complex, Russia,
  - Kondopoga Pulp & Paper Combinat, Russia,
  - Soll Kamsk Pulp & Paper Combine, Russia,
  - Balakhna Pulp & Paper Combine, Russia,

The following exporters filed response to the questionnaire within the extended time:

- Abitibi-Price inc. (hereinafter referred as Abitibi);
  - Stone Consolidated Corp., USA (hereinafter referred as Stone Consolidated).
- j. A number of exporters, Importers and consumers requested for extension of time, which was allowed by the Authority till 28.2.1997;
- k. The Embassies of USA, Canada and Russia in New Delhi were informed about the initiation of the investigation, in accordance with rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and exporter's questionnaire was sent to the Embassies also alongwith a list of known exporters/producers;

- l. The questionnaire was sent to the known indenting agents and importers of newsprint in India, calling for necessary information in accordance with rule 6(4);
- m. A number of importers/ consumers of newsprint in India requested for copies of the Initiation notification, questionnaire and/or extension of time for filing response. The extension of time was allowed upto 28th Feb., 1997. The Authority, however, holds that there is no provision for obtaining or waiting for responses from all the interested parties or giving any additional time to those interested parties from whom the Authority had not called for information in the first instance.
- n. Information regarding the domestic industry was sought from the petitioners. The petitioners furnished information in respect of the following:
  - Mysore Paper Mills Ltd. (MPM),
  - Nepa Ltd (Nepa),
  - Tamil Nadu Newsprint and Paper Ltd. (TNPL),
  - Hindustan Newsprint Ltd. (HNL).
- o. Information deemed necessary for the purpose of preliminary findings was verified by the Authority;
- p. Cost investigations were also conducted for the purpose of preliminary findings to work out optimum cost of production and cost to make and sell newsprint in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner so as to ascertain if anti dumping duty lower than the dumping margin would be enough to remove injury to the domestic industry;
- q. The investigation was carried out for the period starting from 1st April, 1996 to 31st Oct., 1996;

## **B. PETITIONERS' VIEWS**

2. The petitioners have raised the following major issues in their petition and in their subsequent submissions:

### **On dumping:**

- The newsprint industry is passing through an unprecedented crisis due to large scale dumping of newsprint from USA, Canada and Russia;
- The dumping of newsprint coupled with the fall in the international prices has injured the Indian newsprint industry;

- With the changes in the Government policies, the North American and Russian manufacturers of newsprint reduced their prices drastically;
- The normal value of newsprint in the North America is established by the prices confirmed by a producer in Canada. The petitioner furnished a number of quotations in the domestic market of Canada and USA. The petitioner claimed that the same level of normal value should be considered in case of USA and Canada and the two may be considered as a territory.
- The petitioner furnished a number of quotations to establish export price in support of its allegation of dumping. The quotations with regard to prices in the domestic market and export price to India were at nearly the same point of time (the time lag in the quotations is as low as one day);
- There is dumping of newsprint by the North American producers to an extent of US \$ 250 per MT;
- In case of Russia it was submitted that the Authority should consider the normal value based on cost of production constructed for Russian producers, on the basis of international prices of Pulp;

On injury :

- In spite of reduction in the selling prices by the domestic producers, there was a sharp increase in the quantum of imports from these countries, resulting in very poor sales and capacity utilisation of the domestic producers;
- Some of the Indian producers have been forced to completely stop or significantly curtail production of newsprint;
- The increase in imports in absolute terms, market share of imports vis-à-vis domestic share, and the fall in the capacity utilisation are a direct consequence of injury to the Indian industry caused by the dumped imports.

**C. VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES**

3. The views expressed by exporter, importers and other interested parties, who have responded to the Authority, are as under:

**I. Canadian High Commission:**

**1) On dumping:**

- a) The evidence of dumping provided by the petitioner is uncertain and not clear.



- b) The complaint shows that, world-wide, the prices for pulp and paper products are declining. The fact that prices in the North American domestic market and exports to India are declining is an indication that dumping may not be occurring.
- c) There are discrepancies between the normal value used in various places in the complaint.
- d) The petitioner has assumed that the prices prevailing in the exporters' domestic market do not warrant adjustments.
- e) There is no information in the petition relating to selling prices in the Canadian market. The complaint generally refers to a North American market, rather than the two independent countries in North America.

II) On injury and causal link :

- a) There is little evidence in the petition to show that the injury suffered is being caused by dumping.
- b) The export prices from Canada are still higher than prices in 1994-95. This fact does not support the allegation that the foreign suppliers drastically reduced their prices after Jan., 1996. The complainants have lost sales and market share for reasons other than dumping.
- c) There is evidence in the petition that injury may have been caused by other factors. For instance, various import restrictions were lifted over the years, enabling the foreign suppliers to enter the market. The consumers may have shifted to foreign producers for other reasons, such as quality, timeliness, dependability of supply. One producer had its annual shut down in July, which might have caused supply problem for customers.
- d) The fact that some companies in India have closed is an indicator of injury, not necessarily linked to dumping. The closure could be inability of these producers to compete with fairly traded foreign goods. The consumers might have moved to foreign supply as the same were stable, long-term source.
- e) The standing of the Authority with regard to confidentiality of information is not clear.

II. Abitibi-Price Inc:

- a) The export price to India were not materially lower than the range of domestic ex-works prices or export price to other world markets;
- b) The cost and profitability for Abitibi's Chandler Mill regarding exports to India and sales in the home market are nearly identical and higher than profitability on exports to rest of the world;



- c) The cost and profitability for Abitibi's Grand Mill are difficult to be compared for exports to India and domestic sales, as there were no domestic sales;
  - d) Abitibi's price adjustments during the investigation period were in response to market demand from the customers;
  - e) There will be some variations in the profitability levels achieved by the company on mill by mill basis.
- iii. Stone Consolidated Corp., Canada: The exporter was not originally addressed by the Authority. It requested for a copy of the petition and questionnaire and filed its response. The views expressed are:
- a) Newsprint has been shipped from European countries at dumped prices;
  - b) USA and Canada are separate countries and should be treated separately;
  - c) The petitioner has indicated ocean freight and inland freight both as US \$ 130 per MT, which is incorrect and extremely high;
  - d) The petitioner has based evidence of dumping on list prices, which is not the price at which the business is transacted;
  - e) There are various contradictions in the petition.
  - f) The petitioner has not brought out how the domestic industry has suffered injury as a result of alleged dumping. There is no reference to causal link in the petition;
  - g) Imports of newsprint in India were largely controlled and were subjected to quantitative restrictions;
  - h) The prices of newsprint declined in the international market;
  - i) The newsprint industry has cyclical rise and fall in the prices;
  - j) The Government of India has imposed 10% import duty on newsprint;
  - k) The low capacity utilisation is a direct consequence of inability of the domestic industry to compete on the basis of international prices;
  - l) The Indian industry was holding high level of stock subsequent to decontrol of imports in May, '95 and even in Feb., '96, when the prices were very high.

IV. Mekor International Consortium, Russia (Mekor): While expressing concern at the lower prices of newsprint prevailing in the Indian market, the exporter has given only a brief history of newsprint market in India.

V. Importers/Consumers/Other interested parties:

i) On dumping:

a) The prices of newsprint started declining world-wide from April, '96 due to forces of demand and supply;

b) Even after decontrol of imports, prices of newsprint increased in the Indian market;

c) The prices of newsprint during the investigation period declined continuously. A month-by-month comparison clearly establishes link between the US prices with the import prices;

ii) On injury:

a) Increased imports of newsprint are related to other factors, such as quality, dependability and timely supply;

b) The petitioner has neither quantified injury nor presented any descriptive account of the injury suffered. Normal price variations do not tantamount to injury;

c) The Indian industry has made healthy profits even in the investigation period;

iii) Others

a) Provisions of the Anti-dumping Act and Rules do not apply. The said provisions are ultra-vires, imposes restrictions on the right of the consumers to carry on trade and business and discriminates between the newsprint producers and consumers;

b) The consumers would try to purchase at prices which would lower their production costs;

#### D. EXAMINATION OF THE ISSUES RAISED

4. The submissions made by the exporters, importers, petitioner, consumers and other interested parties have been examined and considered and have been dealt at appropriate places in this notification.

#### E. PRODUCT UNDER CONSIDERATION & SCOPE OF INVESTIGATION

5. The product considered in the present investigation is newsprint. Newsprint is an uncoated paper of a kind used for printing of newspaper, of which not less than 65% by weight of the total fiber

content consists of wood fiber obtained by a mechanical or chemi-mechanical process, unsized or very lightly sized, having a surface roughness Parker Print Surt (1 Mpa) on each side exceeding 2.5 micro meter (micron), weighing not less than 40 gsm and not more than 65 gsm. Newsprint is classified under chapter 48 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

#### **F. LIKE ARTICLES**

6. Some of the interested parties have argued that the newsprint has been imported from the said countries on account of its better quality. It is, however, not disputed by these interested parties that the newsprint produced and sold by the domestic industry and imported from these countries have been used interchangeably. The pattern of imports from these countries and sales by the domestic industry clearly establish that the newsprint imported from the subject countries substituted newsprint produced and sold by the domestic industry -- both technically and commercially. The newsprint produced and sold by the domestic industry is, therefore, considered as like article to the newsprint imported from the subject countries within the meaning of the rule 2(d).

3

#### **G. DOMESTIC INDUSTRY**

7. The petition has been filed by Indian Newsprint Manufacturers Association (INMA), D-165, Defence Colony, New Delhi-110024. The petition is, therefore, considered as having been made on behalf of the domestic industry.
8. The Association has furnished information with regard to the domestic industry in respect of units which account for a major proportion of the total domestic production of newsprint in India during the investigation period. These units collectively constitute domestic industry in accordance with Rule 2(b) supra.

#### **H. NORMAL VALUE**

9. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:
- (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
  - (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the

sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

10. Argument has been raised that there was no proper evidence in the petition and the very basis on which the investigations were initiated was not proper. The Authority observes that the onus on the petitioner is to establish a *prima facie* case. The petitioner is obliged to furnish evidence as is reasonably available to it. In the instant case, the petitioner furnished evidence of normal value on the basis of prices prevailing in the territory. The petitioner has furnished evidence of the prices prevailing in the territory on the basis of prices published in a leading journal. The same are not on the basis of list prices. It is appreciated that the prices published in the journal need not be ex-works realisations and may warrant adjustments. However, the Authority found that the differences in the normal values calculated on the basis of the published prices and export prices on the basis of ex-works realisations were significant enough to take into account expenses which the exporters may have to incur on sales in home market. The Authority, therefore, holds that there was sufficient *prima facie* evidence before the Authority with regard to normal value to justify investigations. The Authority has determined for the purpose of these preliminary findings, as detailed hereinbelow, normal value in case of Canada based on the actual net realisations by the exporters from Canada on the basis of the information furnished by these exporters.
11. Argument has been raised that the petitioner has claimed incorrect and extremely high adjustment on account of ocean freight and inland freight in the exporting country(ies)(s). Since the adjustment with regard to ocean and inland freight are being allowed on the basis of

amounts claimed by the exporters, the amounts claimed by the petitioner are irrelevant.

12. The Authority sent questionnaire to the exporters to furnish information in accordance with the section cited above so that the normal value could be worked out. The normal value in case of those exporters who have furnished information has been worked out on the basis of information furnished by them and the same is explained hereinbelow:

(I) Abitibi:

- i) Abitibi filed separate response in respect of its Mills in USA and Canada. The exporter argued that:
- a) The cost and profitability for Abitibi's Chandler Mill on exports to India and sales in the home market are nearly identical and higher than profitability on exports to rest of the world;
  - b) The cost and profitability for Abitibi's Grand Mill are difficult to be compared for exports to India and domestic sales, as there were no domestic sales;
  - c) Abitibi's price adjustments during the investigation period were in response to market demand from the customers;
  - e) There will be some variations in the profitability levels achieved by the company on mill by mill basis.

The Authority observes that the exporter has pleaded no dumping on the grounds of cost and profitability. The argument of the exporter is not tenable in view of the relevant provision of law. For dumping, only the normal value in the exporter's domestic market and the export price to India are relevant.

ii) The argument of the exporter that there may be some variations in the Mill by Mill profitability is also not tenable. The normal value has to be determined in accordance with the prices of the Mill in question in the two markets. Since the exporter has distinctly separate pricing in Canada and USA, the exports made from USA and Canada have to be treated separately. Therefore, in case of Abitibi, normal values and export prices have been determined separately for Canada and USA in the following paragraphs.

iii) The exporter has furnished detailed information with regard to its selling prices in the domestic market. The information has been furnished on month to month basis, as requested by the Authority. Since the exporter has furnished its selling prices in the domestic market, the normal value has been arrived at in accordance with Section 9A(1)(c)(i).

iv) Abitibi has been claimed the following adjustments in the prices in the domestic market:

a) Discounts: The exporter has claimed that it had paid discounts on the list price of US \$ 780 per MT. The discounts increased from US \$ \*\*\* (Jan-Mar., 1996) to US \$ \*\*\* per MT (Oct., 1996). Since the exporter has allowed discounts on sales made in the domestic market, the same have been allowed for the purpose of preliminary determination.

b) Inland freight: The exporter has argued that the inland freight varies from customer to customer, depending upon the distance involved. The exporter has claimed a range of inland freight cost incurred, instead of a single value. The Authority observes that the rules governing comparison requires due allowance to be given for all factors which affect price comparability. The exporter should have claimed adjustment on the basis of average inland freight cost incurred by it. Since the exporter has not claimed average freight, the same has been allowed on the basis of lowest freight cost incurred.

v) The Authority has allowed these adjustments for the purpose of preliminary determination, except as detailed in the foregoing. The adjusted prices have been considered as net ex-works realisations.

(II) Stone Consolidated: Stone Consolidated has claimed the following adjustments in the domestic prices:

- Discounts,
- Inland freight from warehouse to customers in domestic market;
- Inland freight from mill to warehouse on equalised basis.
- Difference in selling expenses;
- Difference in production costs because of batch process.

The basis of claiming adjustments on account of above are as under:

a) Discounts: The exporter has claimed discount ranging between US \$ \*\*\* (April, 1996) to US \$ \*\*\* (Oct., 1996) per MT. This adjustment has been allowed on monthly basis.

b) Inland freight: The exporter has claimed that it has sold in the domestic market from its warehouses and has incurred an expenditure of US \$ \*\*\* (April, 1996) to US \$ \*\*\* (Oct., 1996) on freight from its warehouses to customers. The exporter has further claimed that it has incurred an expenditure of US \$ \*\*\* per MT on freight from its plant to warehouses, on equalised basis.

c) An adjustment of US \$ \*\*\* per MT on account of selling expenses has been claimed, being the additional selling expenses on account of sales to the domestic market.



d) An adjustment of US \*\*\* per MT on account of difference in product costs has been claimed on the ground that the sales in the home market are of smaller lots and the customers take "just-in-time" deliveries. The exporter has argued that it has to produce in batches for sales in the home market. Contrary to this system of sales in the home market, the exporter has further argued that exports to India are in large volume and the mills can produce newsprint continuously for much longer duration. The exporter has argued that a machine which normally operates at \*\*\*% efficiency in batch production would operate at \*\*\*% efficiency in continuous production, resulting in a difference of \*\*\*% in production. The exporter has, therefore, concluded that there is an additional cost involved in case of sales in the home market, which has been estimated to as US \$ \*\*\* per MT, considering average fixed cost of C\$ \*\*\* per MT.

The exporter has not furnished any evidence to establish that there will be a difference in efficiency in batch and continuous production process. Moreover, it is also not clear from the documents submitted by the exporter that it has to produce in batches when the party has claimed that it has despatched goods from warehouses. The claim of the exporter is, therefore, not accepted.

Though the above contentions of the exporter requires detailed verification, the Authority has allowed claims at (a) to (c) for the purpose of preliminary determination.

(III) Other exporters from Canada and USA:

M/s. McCarthy Tetrault, Canada replied vide fax dated 3rd April, 1997 that it did not receive the enquiry in time and requested for extension upto 15th April, 1997.

The Authority observes that under Rule 6(4), the Authority may issue a notice calling for information from the exporters, foreign producers and such information shall be furnished by such persons within thirty days from the date of receipt of the notice. The notice is deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the Embassy of the exporting country. The Authority, therefore, holds that it would have been inappropriate to grant extension of time requested by McCarthy Tetrault, Canada. The Authority would, however, consider the response, if furnished, for definitive determination.

The other producers/exporters from Canada and USA have failed to respond to the Authority. The Authority holds that the other exporters/producers from Canada and USA failed to co-operate with the Authority and the preliminary findings have been announced in accordance with Rule 6(8).

Scrutiny of the information furnished by the importers reveals that the following parties have also exported newsprint to India during the investigation period.

- a) Price & Piece, 21-A, Neil Road, Singapore;
- b) Avenor Inc., 1250, Rene-Levesque Blvd West, Montreal, Quebec, Canada;
- c) Daishowa Forest Products, Canada.

Since these exporters have not co-operated with the Authority, the normal values considered at the time of initiation have been considered. Since there is reasonable evidence that the exporters have paid freight on sales made in home market, an adjustment on account of the same has been allowed at US \$ 40 per MT.

- (IV) Mekor has not furnished information requested, stating that it had no information on the questions raised. The Authority had clearly stated in the notice calling for information that in case the exporter did not undertake any of the following activities, the notice may be passed on to the party concerned:

- a. produces or manufactures the goods under consideration,
- b. sells in the domestic market,
- c. exports to India,
- d. exports to countries other than India.

In view of the above, Mekor should have transmitted the questionnaire to the concerned party(ies). This was not done by Mekor.

Mekor has, however, expressed concern at the lower prices prevailing in the Indian market and has requested that Government of India should take measures to improve the same.

- (V) The Trade Representation of Russian Federation in India requested vide letter dated 30.12.1996 that the Authority may issue notice calling for information to the Ministry of Foreign Economic Relations, Moscow, Russia. The Authority accordingly issued notice to the Ministry of Foreign Economic Relations, Moscow, Russia as also to the Trade Representation of Russian Federation in India. The Authority however, notes that none of the exporters/producers from Russia has furnished information in the prescribed format. The Authority holds that the exporters/producers from Russia have failed to co-operate with the Authority and preliminary findings are being announced in accordance with Rule 6(8). Since none of the exporters has responded, the Authority has determined normal value on the basis of cost of production constructed for Russia. The cost of production was earlier constructed for Russia at the time of initiation. The Authority has considered the same level of normal value for preliminary



determination also in view of non-co-operation from the exporters/producers from Russia.

## **I. EXPORT PRICE**

13. In case of Abitibi and Stone Consolidated, the Authority has determined the export price on the basis of submissions made by the exporters. The export price has been arrived at as detailed hereinbelow:

14. **Abitibi:**

The exporter has furnished separate details of exports made by it from Canada and USA. The exporter has furnished transaction-wise details of exports made from the two countries, on the basis of invoice dates. The month-wise CIF export price has been worked out on the basis of details of month-wise exports furnished by the exporter. The exporter has claimed the following adjustments:

a) Inland freight : An amount of US \$ \*\*\* per MT has been claimed in case of exports made from US mills, whereas an amount of US \$ \*\*\* per MT has been claimed in case of exports made from Canada;

b) Ocean freight: An amount of US \$ \*\*\* per MT has been claimed in case of exports made from US mills, whereas an amount of US \$ \*\*\* per MT has been claimed in case of exports made from Canada;

c) Commissions: The exporter has claimed that it has paid discount @ \*\*\*% in case of exports from US and @ \*\*\*% in case of exports from Canada. It is found from the transaction wise details that the exporter has paid commissions ranging between \*\*\*% and \*\*\*% in case of exports from Canada. Majority of transactions are with \*\*\*% commission. The Authority considers it appropriate to allow the claim with regard to commission.

The Authority considers it appropriate to allow the adjustments from (a) to (c) for the purpose of preliminary findings.

15. **Stone Consolidated:**

a) Stone Consolidated has exported newsprint to India at US \$ \*\*\* per MT in \*\*\*, 1996 and at US \$ \*\*\* per MT from \*\*\*\*, 1996, whereas the prices of the exporter in the domestic market declined in each month of the investigation period.

b) The exporter has stated that it has made all exports to India through their sole agents, Universal Paper and there was no agent in India. The exporter has further stated that it paid commission to Universal Paper @ \*\*\*% on ex-works price. The exporter has furnished details of ocean freight and inland freight paid by it on exports to India. Adjustment with regard to ocean freight has been claimed on the basis

of actual ocean freight payable/paid by the exporter. Adjustment with regard to inland freight is based on freight cost per container and average load per container.

- c) The ex-works export price has been worked out from the above information given by the exporter.

16. Other exporters from USA and Canada and exporters from Russia:

- a) The other producers/exporters from Canada and USA and all the exporters/producers from Russia have failed to respond to the Authority. The Authority holds that these exporters have failed to co-operate with the Authority and the preliminary determination have been announced in accordance with Rule 6(8).
- b) The export price in case of Avenor, Dalshowa and Price and Piece has been determined from the information given by the importers. The average C&F export price in case of individual exporters has been adjusted for ocean freight, inland freight and commission, on the basis of information furnished by \*\*\* and \*\*\*. Since the exporters have not co-operated with the Authority, the higher of the expenditure incurred by \*\*\* and \*\*\* has been considered.
- c) Export price in case of Russia has been determined on the basis of information compiled by the Directorate of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta. Since none of the exporters from Russia has co-operated with the Authority, export price in case of individual exporters has not been determined. The C&F export prices have been adjusted for ocean freight and commission. The petitioner has claimed ocean freight @ US \$ \*\*\* per MT and commission @ \*\*\*%. It is, however, found that highest commission paid is \*\*\*% (by \*\*\*). It is therefore, considered appropriate to allow freight @ US \$ \*\*\* per MT and commission @ \*\*\*%.

J. COMPARISON

17. The rules relating to comparison provides as follows:

“While arriving at margin of dumping, the designated authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability.”

18. Whereas the argument that the international market was declining is recognised and is well appreciated, the same is irrelevant in so far the

issue of dumping by an exporter is concerned. The only relevant issue to decide dumping is the pricing of the exporter in the two different markets. The argument of the interested parties that there was no dumping due to the declining international prices, is not tenable. However, the Authority observes that there was significant decline in the prices in the domestic market also in case of Abitibi and Stone Consolidated. Since the prices in the US and Canadian markets were also declining, any comparison on the basis of averages of normal value and export price for the investigation period as a whole could be misleading. The Authority had, even for the purpose of deciding on initiation, made comparison of normal value with export price on month-to-month basis. The Authority observes from the information furnished by Abitibi and Stone Consolidated that it would be appropriate to make comparison of normal value and export price on month-to-month basis. It is also observed that Abitibi and Stone Consolidated have furnished details of all the export transactions made to India. The export price on this basis has been compared with the normal value in US/Canada so that the comparison is done as nearly as possible at the same point of time.

19. Export price in case of other exporters has been compared with the normal value on similar lines, i.e., month-to-month basis.
20. The comparison shows the following dumping margins:

(all mounts in US \$ per MT)

SN	Name of the Exporter	NV,EP, DM #	April, 1996	May, 1996	June, 1996	July, 1996	August, 1996	Sept. , 1996	October, 1996
1.	Abitibi - exports from USA	NV	***	***	***	***	***	***	***
		EP	***	***	***	***	***	***	***
		DM	25	23	nil	32	33	26	67
2.	Abitibi - exports from Canada	NV	***	***	***	***	***	***	***
		EP	***	***	***	***	***	***	***
		DM	14	3	(-) 4	34	13	15	67
3.	Stone Consolidated	NV	***	***	***	***	***	***	***
		EP	***	***	***	***	***	***	***
		DM	nil	6	0	6	2	(-) 3	nil
4.	Avenor	NV	***	***	***	***	***	***	***
		EP	***	***	***	***	***	***	***
		DM	32	51	61	75	nil	nil	nil
5.	Daishowa	NV	***	***	***	***	***	***	***
		EP	***	***	***	***	***	***	***
		DM	51	nil	nil	55	nil	nil	nil

SN	Name of the Exporter	NV,EP, DM \$	April	May	June	July	August	Sept.	October
6.	Price & Piece-exports from Canada	NV	***	***	***	***	***	***	***
		EP	***	***	***	***	***	***	***
		DM	17	32	30	42	24	51	nil
7.	Price & Piece-exports from USA	NV	***	***	***	***	***	***	***
		EP	***	***	***	***	***	***	***
		DM	56	38	nil	nil	nil	nil	nil

# NV: normal value,

EP: export price,

DM: dumping margin as percentage of export price.

Nil figure in respect of dumping margin indicate nil imports resulting in nil dumping margin.

**K. INJURY**

21. Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of Injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, "...taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such Imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped Imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such Imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
22. Rule (iii) of the Annexure II to the Rules requires that in case Imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping Investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports. Such assessment can be, however, made only if it is determined that:
- a) the margin of dumping in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the import of the like article in India, and
  - b) the cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article.

In the present case, the dumping margin in respect of each exporter as also each country is more than the limits prescribed. Further, cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article. The Authority has, therefore, cumulatively assessed the effects of these imports on the domestic industry.

23. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II (iv) of the rules supra.
- a. Volume and Market Share of Dumped Imports
    - i) Volume of dumped imports:  
Imports of newsprint in India increased from 217108 MT (1992-93) to 301967 MT (1995-96) and were 382861 MT in the seven months of investigation period (656333 MT on annualised basis). Imports from the

subject countries collectively increased from 108330 MT (1992-93) to 228899 MT (1995-96) and were 284995 MT in the investigation period (488563 MT on annualised basis). Imports from the subject countries increased by 351% in absolute terms in the investigation period as compared to 1992-93, as may be seen from the following figure 1.

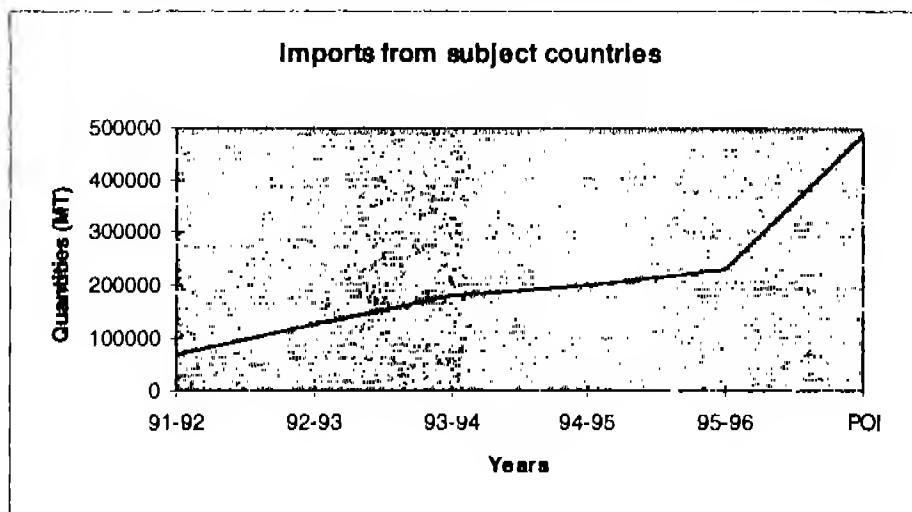


Figure 1 - Imports of newsprint from the subject countries

ii) Market share:

Share of the subject countries in the total imports in the country increased from 50% (1992-93) to 74% (investigation period). Market share of the subject countries in the total demand of newsprint in India increased from 21% (1992-93) to 32% (1995-96) and to 54% in the investigation period as may be seen from the following figure 2.

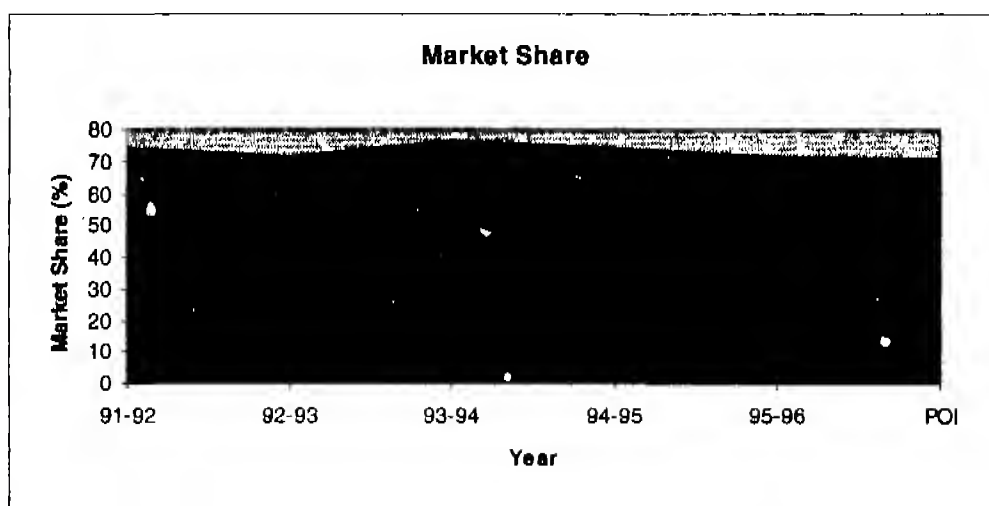


Figure 2 - Market share of imports from the subject countries and sales by the domestic industry



b. Factors affecting domestic industry:

i) Production and Capacity Utilisation:

Production of the domestic industry remained between 2.80 lacs and 2.90 lacs between 1992-93 and 1995-96. The production increased in the investigation period by 12%. It is, however, found that TNPL has added substantial capacity (by 50000MT). Domestic Industry lost market share from 47% (1992-93) to 40% (1995-96). The market share, however, sharply declined to 17% in the investigation period, as may be seen from the figure 2 above.

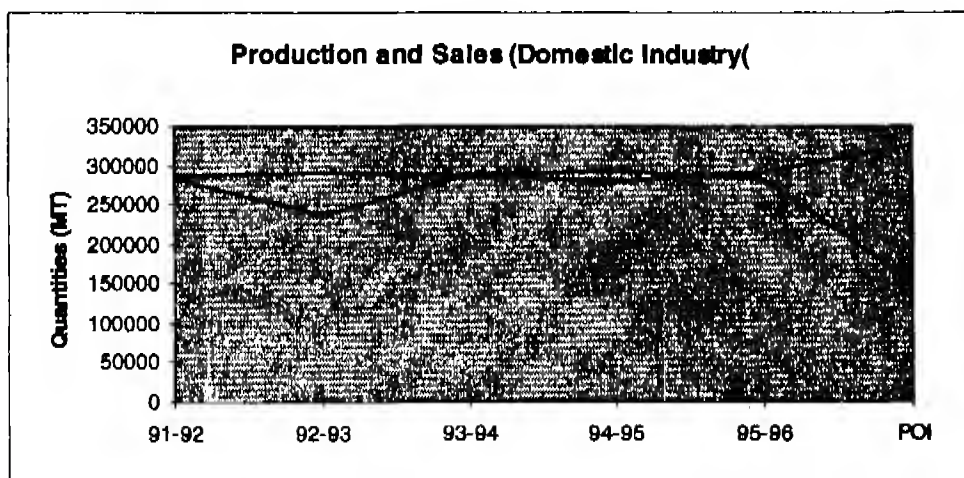


Figure 3 - Production and sales of the domestic industry

Petitioner reported that M/s. Nepa Ltd., Danalakshmi Paper Mills Ltd., and Aurangabad Paper Mills Ltd. have suspended production in view of dumping.

ii) Sales in Absolute Quantity:

Sales of the domestic industry in absolute volumes remained between 2.70 lacs MT and 2.95 lacs MT between 1992-93 and 1995-96. The sales however, sharply declined by 46% in the investigation period on annualised basis, as may be seen from the figure above.

iii) Selling Prices Trend:

The domestic industry was not able to sell its produce in view of cheaper imports from the subject countries. The consumers demanded lower prices and higher discounts in view of cheaper produce available from other sources. Increasingly lower prices offered by the exporters in the investigation period forced the domestic industry to offer higher discounts, which resulted in price undercutting in the Indian market. It is also observed that the international prices of major raw material "Pulp" were declining during the investigation period. However, the available data reveals that the decline in the selling prices in the investigation period is significantly higher than the decline in the cost of production.

- iv) **Stocks:** Month-end stocks with the domestic Industry indicate increasing trends during the investigation period, as may be seen from the figure 4. Nepa had saleable stocks of newsprint. The shutdown of the company can not be a reason for the exporters to dump the goods in India.

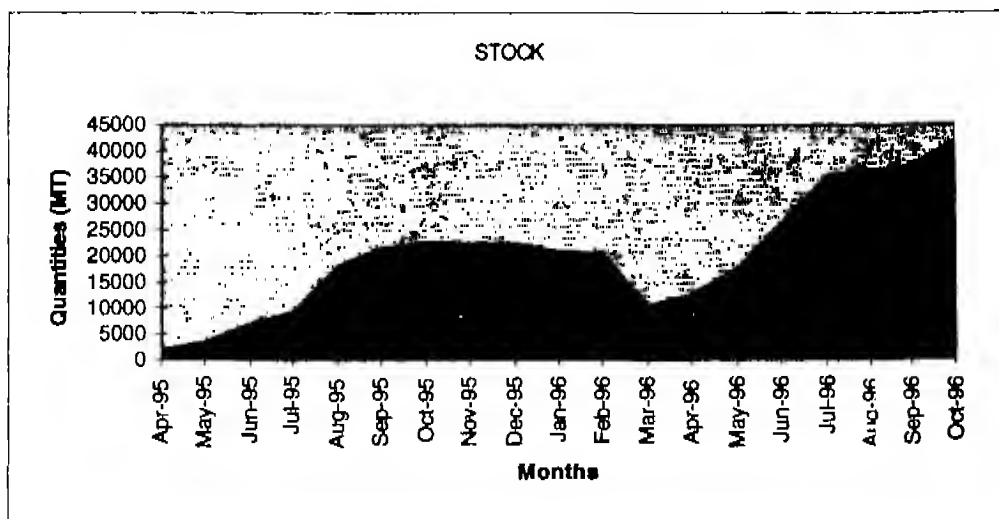


Figure 4 - Stock of newsprint with the domestic industry

- iv) **Profit/Loss:**  
The domestic industry was making profit prior to the investigation period. The domestic industry, however, suffered financial losses in the investigation period from sale of newsprint at prices below cost of production with reasonable profits.
- vi) **Conclusion on injury:** The Authority concludes from the foregoing that:
- i) The imports from the subject countries have increased in absolute terms;
  - ii) The exporters entered in contracts for supplies of newsprint at increasingly lower rates for deliveries to be made in the subsequent months. This forced the Indian industry to reduce its prices, significantly below cost of production and reasonable profit ;
  - iii) The imports from the subject countries resulted in price undercutting in the Indian market;
  - iv) Sales of domestic industry declined steeply in the investigation period;

v) Stocks of newsprint with the domestic Industry show increasing trend in the investigation period.

24. It is thus seen the domestic industry has suffered material injury from imports originating from the subject countries.

#### **L. CAUSAL LINK**

25. In determining whether material injury to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts:

(i) The Imports of the product from the subject countries increased significantly in absolute terms and relative to the production and consumption of the product in India. The share of the subject countries in the total Imports also increased significantly. As a direct consequence, the domestic industry lost market to a significant level.

(ii) The substantial imports of newsprint from the subject countries at dumped prices forced the domestic industry to reduce its selling prices to unremunerative levels and resulted in a situation of price undercutting in the Indian market. The sales below cost of production resulted in financial losses to the domestic industry.

26. The Authority thus arrived to a conclusion that the material injury to the domestic industry was caused by the dumped imports from the subject countries.

#### **M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

27. The purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

28. It is recognised that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using newsprint and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures, particularly if the levy of the anti dumping duty is limited to the amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and would not affect the availability of the product to the consumers.
29. To ascertain the extent of Anti-dumping duty necessary to remove the injury to the domestic industry, the Authority has relied upon reasonable selling price of the newsprint in India for the domestic industry, by considering the optimum cost of production and reasonable profit for the domestic industry.
30. The import duty imposed by the Government of India has relevance in determination of the extent of injury suffered by the domestic industry and has been accordingly taken care of.
31. It is appreciated that the newsprint industry is cyclical in nature and has periodical rise and fall. However, dumping is determined with reference to the normal value and export price at nearly same point of time, as brought out above under comparison. The cyclical nature of industry is, therefore, irrelevant for deciding dumping.
32. With regard to confidentiality of information furnished by an interested parties, it is clarified that the rules relating to confidentiality prescribe that in case the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information. There is typographical error in the exporter's questionnaires sent and the word "regard" may be substituted by "disregard".

#### **N. CONCLUSIONS**

33. The Authority concludes, after considering the foregoing, that:
  - a. Newsprint originating in or exported from USA, Canada and Russia has been exported to India below its normal value, resulting in dumping;
  - b. Imports of newsprint from these countries have caused material injury to the domestic industry;

- c. The injury has been caused by the imports from the subject countries.
34. It is considered necessary to impose anti dumping duties provisionally, pending final determination, on all imports of newsprint originating in or exported from the subject countries in order to remove material injury to the domestic industry, pending investigation.
35. It was considered whether a duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove the injury. The weighted average landed price of the imports for each exporter, for the purpose, was compared with the fair selling price of the domestic industry, determined for the period of investigation. Wherever the difference was less than the dumping margin, a duty lower than the dumping margin is recommended. Accordingly, the Authority recommends that provisional anti dumping duties, as set out below be imposed, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of newsprint, falling under Chapter 48 of the Customs Tariff, originating in or exported from these countries, pending final determination.

Products originating in or exported from	Name of the exporter	Amount of Duty (Rs. per MT)
1. USA	a. Abitibi-Price Inc.	6250
	b. Price & Piece,	2513
	c. Exporters other than above	6250
2. Canada	a. Abitibi-Price Inc.	3089
	a. Stone Consolidated Corpn.	1041
	b. Daishowa Forest Products	2692
	c. Price & Piece,	5160
	d. Exporters other than above	5160
3. Russia	Any exporter	3191

36. The known exporters, importers, petitioners and other interested parties are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of the despatch of the letter. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings.

DIPAK CHATTERJEE, Designated Authority